*स्थानिक से वैश्विक: एमएसएमई के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका**

श्री स्वामीनाथन जे.

विशिष्ट अतिथिगण, देवियो और सज्जनो। आप सभी को नमस्कार !

एफईडीएआई के वार्षिक दिवस पर इस प्रतिष्ठित सभा में बोलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा व्यापार की जटिलताओं को स्पष्ट करने और विनियामकों के साथ एक महत्वपूर्ण आवाज़ के रूप में काम करने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से, एफईडीएआई ने भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार के नियमों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए, जब मुख्य कार्यकारी श्री सिंधवानी ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, तो मुझे पता था कि यह एक ऐसा अवसर है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता।

जैसा कि हम एफईडीएआई की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, यह भारत के आर्थिक भविष्य के लिए समष्टि दृष्टिकोण पर विचार करने का भी एक उपयुक्त अवसर है। 2022 में, जब हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने देश के लिए पाँच प्रमुख संकल्पों को रेखांकित किया, जिनमें से एक 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी क्षेत्रों में एकीकृत प्रयास की आवश्यकता होगी, जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एमएसएमई, जिन्हें अक्सर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, राष्ट्रीय चैंपियन बनने की अपार क्षमता रखते हैं - ऐसी क्षमता जिसका अभी तक बड़े पैमाने पर दोहन नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने आज अपने संबोधन के लिए *'स्थानिक से वैश्विक: भारत के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका'* विषय चुना है।

* 21 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) के वार्षिक दिवस पर उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे. का भाषण।

भारत की आर्थिक संवृद्धि में एमएसएमई की भूमिका

लगभग 63 मिलियन इकाइयों के विशाल नेटवर्क के साथ, एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई का योगदान देते हैं और इसके विनिर्माण उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देते हैं।[1]

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसएमई क्षेत्र की उद्यमिता को बढ़ावा देने और पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने में महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण सहायक इकाइयों के रूप में, एमएसएमई बड़े उद्योगों का समर्थन करते हैं और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लाखों नौकरियों के सृजन के साथ, एमएसएमई क्षेत्र भारत में रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जो आजीविका को बनाए रखने और समावेशी संवृद्धि को आगे बढ़ाने में इसके महत्व को रेखांकित करता है।

एमएसएमई क्षेत्र का प्रभाव घरेलू सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, इन उद्यमों ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता साबित की है, जो भारत के निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। वैश्विक बाजारों में इसकी बढ़ती उपस्थिति भारतीय एमएसएमई उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती स्वीकृति और मांग को दर्शाती है, जो इस क्षेत्र को भारत के वैश्विक आर्थिक पदचिह्न को बढ़ाने में एक प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित करती है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर *"मिसिंग मिड्ल"* का मुद्दा। जबकि सूक्ष्म उद्यम एमएसएमई के अधिकांश रोजगार का निर्माण करते हैं, वे अक्सर छोटे या मध्यम आकार की फर्मों में बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। यह सीमा पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने, अचल संपत्तियों में निवेश करने और नवीन तकनीकों को अपनाने की उनकी क्षमता को बाधित करती है। आज अपने संबोधन में, मैं इन चुनौतियों पर ध्यान

[1] सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर 2023 को जारी प्रेस प्रकाशनी के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) की हिस्सेदारी 29.15 प्रतिशत थी और इसी अवधि के लिए अखिल भारतीय विनिर्माण जीवीए में एमएसएमई विनिर्माण जीवीए की हिस्सेदारी 40.83 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी 43.59 प्रतिशत थी।

केंद्रित करूंगा और पता लगाऊंगा कि वित्तीय क्षेत्र उन्हें ठीक करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे एमएसएमई के विकास और विकास को बड़े निगमों में समर्थन मिल सके।

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियां

मैं आज एमएसएमई के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप उनमें से ज़्यादातर के बारे में जानते होंगे, इसलिए मैं सिर्फ़ चार मुख्य मुद्दों पर ही बात करूँगा।

वित्त तक पहुंच

पहला मुद्दा किफायती वित्त तक पहुंच है। एमएसएमई के विकास के लिए ऋण महत्वपूर्ण है, और किफायती फंड उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं। बैंक अक्सर परिसंपत्ति-आधारित ऋण का उपयोग करते हैं, जो नकदी प्रवाह के बजाय संपार्श्विक पर निर्भर करता है। हालांकि, कई एमएसएमई के पास संपार्श्विक के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, खासकर कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए, जिससे अक्सर छोटे व्यवसाय औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से वित्तपोषण के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा, चूंकि कई एमएसएमई मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए सूचना विषमता के कारण उनकी ऋण पात्रता का आकलन करना मुश्किल हो सकता है, खासकर उनके व्यवसायों के वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में। हालांकि जीएसटी और डिजिटल भुगतान जैसी पहलों का उद्देश्य एमएसएमई के बीच डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाना है, लेकिन औपचारिक डिजिटल दस्तावेज़ीकरण विधियों को अपनाना सीमित है, जो एक कुशल ऋण हामीदारी प्रक्रिया में बाधा डालता है।

विलंबित भुगतान

दूसरा, एमएसएमई को अक्सर भुगतान में देरी की समस्या का सामना करना पड़ता है। भुगतान प्राप्त करने में देरी से उनका परिचालन चक्र लंबा हो जाता है और मौजूदा ऑर्डर को पूरा करने या नए ऑर्डर प्राप्त करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी के लिए दंड लगाने वाले वैधानिक प्रावधानों के अस्तित्व के बावजूद, एमएसएमई अक्सर इन प्रावधानों का उपयोग करने से बचते हैं। उनकी अनिच्छा कमजोर सौदेबाजी शक्ति और भविष्य के व्यावसायिक अवसरों को खोने के डर के संयोजन से उत्पन्न होती है।

अवसंरचना की अड़चनें

तीसरा, अवसंरचना को बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, एमएसएमई क्लस्टर, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों में महत्वपूर्ण सहायता प्रणालियों का अभाव है। यह कमी न केवल उनके दैनिक कार्यों में बाधा डालती है, बल्कि उनके भविष्य की विकास क्षमता में भी बाधा डालती है। एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने से साझा बुनियादी ढांचा, सेवाएं और बड़े बाजारों तक पहुंच मिल सकती है, जिससे उनकी विकास क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

अनुपालन की आवश्यकताएं

जैसे-जैसे व्यवसाय अनौपचारिक से औपचारिक इकाई में परिवर्तित होते हैं, उन्हें विनियामक दायित्वों और अनुपालन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी इन आवश्यकताओं में कानूनों की व्याख्या, अनुपालन प्रक्रियाओं का ज्ञान आदि शामिल होते हैं। एमएसएमई के विस्तार के प्रयासों के दौरान वित्तपोषण संस्थाओं के साथ कठिनाइयों के उदाहरण असामान्य नहीं हैं। सरकार और विनियामक कठिनाइयों को कम करने और व्यवसाय करने की लागत को कम करने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं।

एमएसएमई को सशक्त बनाने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष आ रही कुछ प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के बाद, तथा वित्तीय क्षेत्र से यहां उपस्थित विशाल श्रोतागण का लाभ उठाते हुए, मैं कुछ ऐसे तरीकों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जिनसे हम इसके विकास और संवृद्धि में सहायता कर सकते हैं।

डिजिटलीकरण और नवीन वित्तपोषण समाधान

अधिकाधिक एमएसएमई द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन लेखा उपकरण अपनाने के कारण, परिणामी डिजिटल फुटप्रिंट वित्तीय संस्थाओं को एमएसएमई के वित्तीय स्वास्थ्य, लेन-देन इतिहास और नकदी प्रवाह पैटर्न पर अधिक सटीक और व्यापक डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है।

हमने पिछले कुछ वर्षों में ऋण वितरण के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है, मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र में और कुछ हद तक एमएसएमई क्षेत्र में। मैं बैंकरों

से एमएसएमई के साथ अपने लेन-देन के अधिक डिजिटलीकरण के लिए इन अवसरों का और अधिक पता लगाने का आग्रह करूंगा। डिजिटल एप्लिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म पारंपरिक ऋण देने से जुड़े कागजी काम और प्रशासनिक बोझ को कम करते हैं, और पूरी पारदर्शिता भी लाते हैं। आवेदन प्रसंस्करण, सत्यापन और संवितरण के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके, वित्तीय संस्थान अनुमोदन के समय को तेज कर सकते हैं और ऋण प्राप्त करने की लागत को काफी कम कर सकते हैं।

बढ़े हुए डिजिटल फुटप्रिंट से प्राप्त डेटा बेहतर जोखिम मूल्यांकन और अनुकूलित वित्तपोषण उत्पादों के विकास को सक्षम करेगा। वास्तव में, एमएसएमई के नकदी प्रवाह की उचित समझ के बाद वित्त प्रदान करना, जिसमें उनके खरीदारों से संभावित विलंबित भुगतानों को शामिल करना शामिल है, वास्तविक कार्यशील पूंजी चक्र का उचित वाचन सुनिश्चित करेगा और पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करेगा। वास्तविक नकदी प्रवाह और उसके समय की अपर्याप्त समझ के परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान कार्यक्रम वास्तविकता के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।

अपनी ओर से, आरबीआई ने एमएसएमई को वित्तपोषण में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। हाल ही में, आरबीआई विनियामक सैंडबॉक्स[2] का तीसरा समूह एमएसएमई ऋण देने के लिए समर्पित था, जहाँ पाँच विचारों को व्यवहार्य पाया गया। इससे पहले, एमएसएमई को विलंबित भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए, आरबीआई ने 2014 में व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) शुरू की थी। यह योजना कई फाइनेंसरों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। जबकि पिछले कुछ वर्षों में लेन-देन में तेजी आई है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्लेटफॉर्म पर अधिक कॉर्पोरेट खरीदारों और एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा ऑनबोर्डिंग में एक लंबा रास्ता तय करना है ।

[2] आरबीआई ने नियंत्रित/परीक्षण विनियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण की सुविधा के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के लिए एक सक्षम ढांचा तैयार किया है, जिसके लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए कुछ विनियामक छूट की अनुमति दे सकते हैं (या नहीं भी दे सकते हैं)। अगस्त 2019 में इसके जारी होने के बाद से इस ढांचे के तहत पाँच समूह हैं।

क्षमता निर्माण और वित्तीय साक्षरता

वित्त और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच के अलावा, एमएसएमई के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई छोटे व्यवसाय मालिकों के पास अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ज्ञान और कौशल की कमी होती है, जो उनके विकास में बाधा बन सकती है।

जबकि आरबीआई एनएएमसीएबीएस[3] कार्यक्रम के तहत बैंकरों के लिए एमएसएमई वित्त पर क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान कर रहा है, मेरा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र एमएसएमई की जरूरतों के अनुरूप क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इन कार्यक्रमों में वित्तीय प्रबंधन, ऋण और विदेशी मुद्रा उत्पादों को समझना और डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। एमएसएमई को सही ज्ञान और कौशल से लैस करके, हम उन्हें संसूचित वित्तीय निर्णय लेने, उनके संचालन को अनुकूलित करने और डिफ़ॉल्ट के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और उद्योग निकायों के बीच साझेदारी यह सुनिश्चित कर सकती है कि ये क्षमता-निर्माण पहल उन व्यवसायों तक पहुँचें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

जैसा कि आप जानते होंगे, भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया है। इस संबंध में, आरबीआई ने सभी राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के संयोजकों को इन पहचाने गए क्लस्टरों की ऋण आवश्यकताओं को अपनी वार्षिक ऋण योजनाओं में शामिल करने की सलाह दी है। इस पहल को और अधिक समर्थन देने के लिए, मैं बैंकों से अनुरोध करूंगा कि वे इन क्लस्टरों के भीतर अधिक एमएसई-केंद्रित शाखा कार्यालय खोलने पर विचार करें, अधिमानतः विदेशी मुद्रा सुविधा के साथ। ये विशेष शाखाएँ न केवल एमएसई के लिए ऋण तक आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करेंगी, बल्कि इन उद्यमों को अनुरूप वित्तीय सलाह और क्षमता निर्माण सेवाएँ प्रदान करते हुए परामर्श केंद्र के रूप में भी काम करेंगी।

[3] बैंकरों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएएमसीएबी)।

एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देना

वित्तीय क्षेत्र, लक्षित समर्थन और अनुरूपित सेवाएं प्रदान करके एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो वैश्विक बाजार में इन व्यवसायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करता है।

प्री- और पोस्ट-शिपमेंट फाइनेंस, फैक्टरिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग जैसे पारंपरिक उत्पादों के अलावा, यह क्षेत्र निर्यात ऋण बीमा और मुद्रा जोखिम हेजिंग समाधानों के माध्यम से एमएसएमई को जोखिमों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण रूप से सहायता कर सकता है। ये वित्तीय साधन न केवल भुगतान चूक और मुद्रा में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि एमएसएमई को नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों की खोज और विस्तार करने का आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं।

मौजूदा नियमों के अनुसार, नकदी और हेजिंग उत्पादों सहित विदेशी मुद्रा की ज़रूरतों को अधिकृत डीलरों के ज़रिए पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख भूमिका होती है। विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति वाले इन बैंकों का यह कर्तव्य है कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करें, खास तौर पर एमएसएमई जैसे छोटे ग्राहकों के साथ।

2019 में एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की शुरुआत का उद्देश्य खुदरा विदेशी मुद्रा लेनदेन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाना था, लेकिन इसमें सीमित सफलता ही मिली है। मैं बैंकों से अनुरोध करूंगा कि वे जागरूकता बढ़ाने और एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं।

क्षेत्र के प्रति संवेदनशीलता

अंत में, अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, वित्तीय क्षेत्र को उनके प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जहाँ वित्तीय अनुशासन महत्वपूर्ण है, एमएसएमई के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियाँ - जैसे कम पूंजी आधार, पैमाने की कमी, विलंबित भुगतानों से नकदी प्रवाह की बाधाएँ, उतार-चढ़ाव वाले बाज़ार की स्थितियाँ और बाहरी आर्थिक दबाव - मूल्यांकन के साथ-साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

जहाँ वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बकाया राशि का समय पर अदायगी महत्वपूर्ण है, वहीं वित्तीय संस्थानों को, पुनर्गठन विकल्प, रियायती अवधि और अनुरूप पुनर्भुगतान योजनाओं; जैसे सहायक उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे एमएसएमई को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते समय उबरने और पटरी पर लौटने के लिए आवश्यक राहत मिल सके।

ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच सहयोग और संवाद से ऐसे समाधान तैयार करने में मदद मिल सकती है जो ऋणदाता के वित्तीय हितों और एमएसएमई की व्यवहार्यता दोनों की रक्षा कर सकें।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: भारत के आर्थिक परिवर्तन की यात्रा हमारे एमएसएमई क्षेत्र के मजबूत विकास के बिना पूरी नहीं हो सकती। एमएसएमई न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, वे विकास, नवोन्मेष और रोजगार के इंजन भी हैं। हालांकि, इन उद्यमों को वास्तव में फलने-फूलने और आगे बढ़ने के लिए, वित्तीय क्षेत्र को अभिनव समाधान, संवेदनशीलता और दूरंदेशी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह केवल ऋण प्रदान करने के बारे में नहीं है; यह इन उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, निर्यात को बढ़ावा देने और 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के देश के लक्ष्य में योगदान देने में सक्षम बनाने के बारे में है। जहाँ वित्तीय साधन और समर्थन तंत्र महत्वपूर्ण हैं, वहीं जिस तरह से हम एमएसएमई क्षेत्र के साथ जुड़ते हैं, यानी उनकी चुनौतियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता और उनकी सफलता के लिए हमारी प्रतिबद्धता अंततः इस साझेदारी की ताकत और स्थिरता का निर्धारण करेगी।

इसके साथ ही मैं मुझे आमंत्रित करने के लिए एफईडीएआई को धन्यवाद देता हूँ और हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजारों के सुचारू संचालन के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका में निरंतर सफलता की कामना करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।